

किसान सशक्त होता है तो गाँव, प्रदेश व देश प्रगति करता है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने सिरोही में किसान सम्मान निधि हस्तानांतरण किया व ग्राम उत्थान शिविर का शुभारंभ किया

जयपुर /सिरोही /जालोर , (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान भारत की आत्मा है। जब किसान सशक्त होता है तो गांव, प्रदेश और देश प्रगति करता है। उन्होंने कहा कि हम संकल्प पत्र में किए गए वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं तथा हमारी सरकार किसानों के कल्याण एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही में कार्यक्रम स्थल पर आयोजित कृषि प्रदर्शनी में सहकारिता, पशुपालन, एफपीओ एवं प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी और एग्री स्टार्टअप सहित अन्य स्टालों का अवलोकन किया।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सिरोही में किसान सम्मान निधि के हस्तानान्तरण एवं ग्राम उत्थान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोगाराम कुमावत, जालोर-सिरोही सांसद लुखाराम चौधरी मौजूद थे।

‘मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की पांचवीं किस्त के रूप में प्रदेश के 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी की, साथ ही 5 लाख किसानों को फसल खराबे पर 327 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया। शर्मा ने समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 1० हजार से अधिक किसानों को 240 करोड़ रुपये की राशि अंतर्गत की गई तथा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ की राशि भेजी गई। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को 75 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्रदान की गई तथा

प्रधानमंत्री आवास योजना के 20 हजार लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये की राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने एक लाख निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतर्गत की। इस दौरान 40 करोड़ रुपये के कृषि उपकरणों का वितरण भी किया गया। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्ष में सिरोही को विकास के लिए अनेक सौगतें दी हैं। इस दौरान ग्राम उत्थान शिविरों का लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से शुभारंभ किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित कृषि प्रदर्शनी में सहकारिता, पशुपालन, एफपीओ एवं प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी एवं एग्री-

स्टार्टअप सहित, अन्य स्टॉल्ल्स का अवलोकन किया। कार्यक्रम में रामलला प्रतिमा का विधिवत पूजन किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने राजस्थान के मूल निवासी एवं महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत राज के. पुरोहित को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, सांसद लुम्बाग्राम चौधरी, विधायक समाराम गरासिया, पुष्पेन्द्र सिंह राणावत, जीवाराम चौधरी, शोभा चौहान, छगनसिंह राजपुरोहित, हमीर सिंह भायल सहित,विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित थे।

ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकियां नाकामयाब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) और ही कहानी कहते हैं। यह सोच-समझकर उठाया कदम नहीं, बल्कि मजबूरी में किया गया फैसला था। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प का दांव उनकी चरम तक जाने की चिरपरिचित शैली का उदाहरण था। अमेरिका के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से उछाली, कभी अस्पष्ट, कभी भड़काने वाले अंदाज में उन्होंने अटलांटिक पार संबंधों में अनिश्चितता पैदा कर दी। भले ही बाद में उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका बल प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन उनका यह दावा कि “ग्रीनलैंड की रक्षा केवल अमेरिका ही कर सकता है”, डेनमार्क और यूरोप की संप्रभुता पर अमेरिकी वर्चस्व की एकतरफा घोषणा जैसा था। यूरोप की प्रतिक्रिया आक्रांश से भरी थी, पर वे इसका हल चाहते थे। डेनमार्क ने ट्रंप के विचार को सिरे से खारिज कर दिया, यूरोपीय संघ ने चुपचाप लेकिन सख्ती से कदम उठाया तथा वॉशिंगटन के साथ व्यापार समझौते के क्रियाव्यवन को रोक दिया। नाटो सहयोगी इस सिद्धांत पर एकजुट हो गए कि आर्कटिक सुरक्षा किसी एक

शक्ति द्वारा तय नहीं की जा सकती, चाहे वह कितनी ही प्रभावशाली क्यों न हो। यूरोप को झुकाने के लिए दी गई ट्रम्प की टैरिफ धमकियाँ भी इस एकता को तोड़ने में नाकाम रहीं। नतीजतन कूटनीति के नाम पर उन्हें यू-टर्न लेना पड़ा। वास्तविक समझौते के बजाय भविष्य के समझौते का दांचा घोषित करके ट्रम्प ने प्रभावी रूप से मानक नीचे कर दिया। टैरिफ इसलिए निर्लंबित नहीं हुए कि यूरोप ने ग्रीनलैंड पर कोई रियायत दी, बल्कि इसलिए कि टकराव एक बंद गली में पहुँच चुका था। इस दांचे ने ट्रम्प को प्रगति का दावा करने का अवसर दिया वो भी बिना स्वामित्व, सैन्य ठिकानों या औपचारिक नियंत्रण के, सिर्फ नाटो के मौजूदा दांचे के तहत अस्पष्ट सहयोग के साथ। दावोस में ट्रम्प का एक घंटे का भाषण प्रभुत्व दिखाने के लिए था, लेकिन उसने उनके रुख के अंतर्विरोधों को और उजागर कर दिया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से अमेरिकी भूमिका का हवाला देकर डेनमार्क को “कृतघन” कहा और आज के दावों को सही ठहराने के लिए ऐतिहासिक शिकायतों का हवाला दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि

अमेरिका ग्रीनलैंड को सिर्फ सुरक्षा के लिए चाहता है, खनिजों के लिए नहीं, जबकि उनकी सरकार अन्य जगहों पर संसाधन-राष्ट्रवाद का समर्थन करती रही है। सबसे उल्लेखनीय यह कि उन्होंने फिर दोहराया कि अमेरिका को नाटो से “कुछ भी नहीं मिलता”, सिवाय यूरोप की रक्षा का बोझ उठाने के। यह तर्क, जो उनके पहले कार्यकाल में भी था। पर अब और भी खोखला लगता है। अगर नाटो से अमेरिका को कुछ नहीं मिलता, तो आर्कटिक सुरक्षा पर उसके महासचिव के जरिए बातचीत क्यों? नाटो-प्रायोजित दांचे की ङ़रूरत ही क्यों? क्योंकि एकतरफावाद के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ट्रम्प ने संबोधन दावोस के श्रोताओं में “दोस्ती” और “कुछ छिपे दुश्मनों” पर मजाक किया। लेकिन हैंसी के पीछे असहजता छिपी थी। यूरोपीय नेताओं ने किसी माहिर सौदेबाज को नहीं, बल्कि ऐसे राष्ट्रपति को देखा, जिसे सामूहिक प्रतिरोध मजबूत होते ही धमकियों से पीछे हटना पड़ा। ग्रीनलैंड प्रकरण में ट्रम्प की मिसाइल रक्षा को लेकर फिर से उभरी दीवानगी,

खासकर उनके प्रस्तावित गोल्डन डोम एंटी-मिसाइल शिल्ड पर भी रोशनी डालता है। रूस के निकट होना, रडार को क्षमता और आर्कटिक पहुँच, ग्रीनलैंड की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति इस सोच में फिट बैठती है। लेकिन यहाँ भी ट्रम्प ने हद से ज्यादा दांव खेला। ग्रीनलैंड को लगभग पूरी तरह अमेरिकी सुरक्षा दृष्टिकोण से परिभाषित करके ट्रम्प ने डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन और यहाँ तक कि ग्रीनलैंड की स्वायत्त सरकार के हितों को भी हाशिये पर डाल दिया। यह रबैया उनके घरेलू समर्थकों को भा सकता है, लेकिन विदेशों में वैधता को कमजोर करता है। आर्कटिक की सुरक्षा संरचनाएँ स्वभावतः बहुपक्षीय हैं, इसके विपरीत दिखावा करना केवल विरोध को मजबूत करता है। असल में, ट्रम्प ने रणनीतिक चिंता को क्षेत्रीय दबाव में बदलने की कोशिश की और पाया कि सहयोगियों की भी अपनी सीमाएँ होती हैं। ट्रम्प बेनकाब हुए हैं? लेकिन न तो घातक रूप से और न ही अपरिवर्तनीय रूप से। ट्रम्प तीन तरह से बेनकाब हुए हैं। पहला, वे एक ऐसे ब्लैफर के रूप में

डोडा सड़क हादसे में दस जवान शहीद

जम्मू, 22 जनवरी। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे में सेना के एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से 1० जवानों की मौत हो गयी और 11 अन्य घायल हो गए।

यहां अधिकारियों ने बताया कि सेना का कैस्पर वाहन भद्रवाह-चंबा सड़क पर थानला के ऊपरी इलाके खत्रीटॉप के पास फिसलन भरी सड़क के कारण, करीब ३०0 फीट गहरी खाई में गिर गया। यह टीएम एक टीएम ऑपरेशन

■ **सैन्य दल एक कार्यवाही के लिए जा रहा था खत्री टॉप के पास सेना का वाहन 300 फीट गहरी खाई में गिर गया।**

के लिए जा रही थी। यह हादसा इतना भयावह था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिला प्रशासन के अनुसार, वाहन में सेना के कुल 21 जवान सवार थे, जिनमें से 1० की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 1० जवानों को ऊधमपुर के कर्मांड अस्पताल में तत्काल उपचार के लिए एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि मामूली रूप से घायल एक जवान का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उपराज्यपाल ने शोक संतोष परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि दुःख की इस घड़ी में पूरा देश एकजुट होकर उनके साथ खड़ा है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस हृदय विदारक त्रासदी पर गहरा दुःख प्रकट किया है। उन्होंने इस घटना को पूरे जम्मू-कश्मीर के लिए एक बड़ी त्रासदी बताते हुए प्रशासन को घायलों के उपचार में कोई कसर न छोड़ने के निर्देश दिए।

केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस दुःख दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा है।

मुम्बई, पुणे सहित 1 5 मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित

राज्य सरकार ने 29 प्रमुख महानगर पालिकाओं के मेयर पद के लिए आरक्षण योजना घोषित की

मुंबई, 22 जनवरी। महाराष्ट्र की राजनीति में स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। राज्य की 29 प्रमुख महानगरपालिकाओं के महापौर पद के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। इस बार के आरक्षण समीकरणों ने राज्य की 1 5 महानगरपालिकाओं की कमान महिलाओं के हाथों में सौंप दी है। मुंबई, पुणे, नागपुर और नवी मुंबई जैसे हाई-प्रोफाइल शहरों में अब सामान्य महिला वर्ग की महापौर चुनी जाएंगी।

29 में से 12 सीटें एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 17 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। शिंदे के गढ़ ठाणे में महापौर एससी कैटेगरी का होगा। मुंबई में 8वीं बार किसी महिला को यह पद मिलेगा। इससे पहले किशोरी पेडनेकर मेयर थीं।

■ **आरक्षण की घोषणा होते ही महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। शिवसेना (यूबीटी) ने इस व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह जताया।**

आरक्षण की घोषणा होते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) की नेता और पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर ने मुंबई महानगरपालिका के आरक्षण पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने सवाल

उठाया कि ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के समय मुंबई महापालिका की पर्ची क्यों नहीं डाली गई? उन्होंने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह व्यक्त किया है। दूसरी ओर, नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने इन आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के तहत अपनाई गई है और इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हुआ है। इस आरक्षण घोषणा के साथ ही, सभी राजनीतिक दलों ने महिला उम्मीदवारों की तलाश और चुनावी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। विशेष रूप से मुंबई और पुणे जैसे शहरों में महिला पार्षदों का कद अब राजनीति में और बढ़ ने वाला है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन को “जैड” सुरक्षा, तेजस्वी की सुरक्षा घटाई

बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव किए हैं

पटना, 22 जनवरी। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के कई दिग्गज विधायकों की सुरक्षा श्रेणी में बड़ा बदलाव किया है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति की ताजा रिपोर्ट और खुफिया इनपुट्स के आधार पर लिए गए इस फैसले में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने तेजस्वी की सुरक्षा घटा दी है, वहीं भाजपा और केन्द्र सरकार के कई मंत्रियों का सुरक्षा घेरा पहले से अधिक मजबूत कर दिया गया है। सुरक्षा समिति की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम कर दी

■ **भाजपा व जद यू के कई वरिष्ठ नेताओं को ज़ैड सुरक्षा दी गई है, वहीं विपक्ष के कई नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई है।**

गई है। अब तक उन्हें ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही थी, जिसे घटाकर अब ‘वाय प्लस’ कर दिया गया है। इसके साथ ही, तीन अन्य वरिष्ठ नेताओं मदन मोहन झा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और राजेश राम की सुरक्षा पूरी तरह से वापस ले ली गई है। एक ओर जहाँ विपक्ष की सुरक्षा में कटौती हुई है, वहीं सत्ता पक्ष के कई रसूखदार चेहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और

बिहार सरकार के मंत्रियों को अब और भी कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केन्द्रीय मंत्री लल्लन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इन्हें वाई से बढ़ा कर वाई प्लस और फिर सुरक्षा मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया गया है।

मध्य प्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हिंदू समुदाय भोजशाला, 11 वीं शताब्दी के इस स्मारक, को वादेवी (देवी सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है।

2003 के ए एस आई आदेश के अनुसार, मुसलमानों को इस स्थल पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुमा की नमाज अदा करने की अनुमति है, जबकि हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पारंपरिक अनुष्ठान करने और प्रत्येक मंगलवार को विशेष प्रवेश का अधिकार दिया गया है।

लेकिन, इस आदेश में उन वर्षों के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती हो। और 23 जनवरी ऐसा केवल चौथा अवसर है, इससे पहले यह संयोग 20०6, 2013 और 2०16 में हुआ था। बसंत पंचमी से पहले धार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

मध्य प्रदेश के इस जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और रैंपिड एक्शन फोर्स सहित लगभग 8,०00 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस पैलैड और वाहन गश्त कर रही है और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है।

इसके अलावा, पूरे शहर में सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है।

‘एआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तात्कालिकता समन्वित नीतियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मांग करती है। बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच, गेट्स ने भारत-अमेरिका साझेदारी को बदलते वैश्विक परिदृश्य में कुछ गिने-चुने भरोसेमंद आधारों में से एक बताया।

उन्होंने बताया, मुझे लगता है कि “अमेरिका और भारत के बीच मजबूत संबंध की तर्कसंगतता अंततः हावी होगी।”

उन्होंने भारत के डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा एआई को तेजी से अपनाने की क्षमता को इसकी प्रमुख ताकत बताया।

ग्रोथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बुनियादी मजबूती में विश्वास को दर्शाता है।

साथ ही, उद्योग जगत सरकार के राजकोषीय समेकन (फिस्कल कन्सॉलिडेशन) के मार्ग के साथ भी सहमत दिखाई देता है। लगभग 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना ​​है कि वित्त वर्ष 2०25-26 के लिए जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि विकास को समर्थन देने वाले उपयोगों के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन पर भी भरोसा कायम है।